A wage goods paradigm is developed on the hypothesis that the wage goods sub-economy is at the core of the economy of a developing country. The economy's residual activities are classified as non-core sub-economy. The wage goods model, the report suggests, should form the core supplemented by mecro economic policies. The market forces should operate partially in order to allow a higher rate of exports, to induct better incentives for production and savings, to reduce Government expenditures, to improve the fiscal health of the economy and to modernise technology. In the wage-goods strategy priority is accorded to the expansion of production capacity of the wage-goods.

(c) and (d) The ideas contained in this report and many other ideas on development and the planning process are kept in view while preparing the Eighth Five Year Plan.

उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से न चलने वाली योजनाएं और परियोजनाएं

2798. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी योजनाएं तथा परियोजनाएं योजनाबद्ध तरीके से नहीं चल रही हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में किन-किन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है और उन्हें क्या-क्या सजा दी गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) योजना का कार्यान्वयन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। योजना आयोग को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि कोई परियोजना योजनाबद्ध तरीके से नहीं चल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Setting up of computer centres in Tamil Nadu

@2799. SHRI R. T. GOPALAN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to establish more computer centres in Tamil Nadu;

(b) if so, the places where such computer centres are likely to be established;

(c) the expenditure likely to be incurred thereon; and

(d) the details of the computer centres already commissioned in Tamil Nadu so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir.

(b) It is proposed to set up National Informatics Centre (NIC) District Informatics Centre at the newly created District: Negapattinam Guaid-e-Nilleth.

(c) An expenditure of Rs. 9.00 lakhs has been estimated on capital infrastructure to establish the above Centre.

(d) In line with its objective to provide computer based services to Central Government Departments, State Governments and District Administrations, NIC has already established Computer Centres in Tamil Nadu as given below:

Location	Computer installed
NIC-Tamil Nadu State Centre Ground Floor, Multi Storyed Building, St. Fort George, Madras-600 009	ND-550 Computer
21 District Informatics Centres in 21 District Headquarters of Tamil Nadu	80386 based Super AT Computer in each District

@Previously Unstarred Question 1255 Transferred from the 5th March, 1992.

Location	*Computer installed*
Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Madras	80486 based Computer.

राज्यों द्वारा गाडगिल-सूत्र का स्वीकार न किया जाना

2800. **श्री ईशदत्त यादव:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों ने गाडगिल-सूत्र को स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा गाडगिल-सूत्र पर क्या-क्या प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) जी, नहीं। कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने फार्मूले में संशोधन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूला निम्नानुसार है:-

I. कुल केन्द्रीय सहायता से, विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए अपेक्षित निधियों को अलग रखकर, जैसा अब किया जा रहा है,

II. शेष में से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए संतुलित धनराशि मुहैय्या कराकर, अर्थात्

(क) पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम,
(ख) जनजाति क्षेत्र,
(ग) सीमावर्ती क्षेत्र, और
(घ) पूर्वोत्तर परिषद

III. दस विशेष श्रेणी राज्यों के लिए शेष राशि में से 30 प्रतिशत राशि रखते हुए, और

IV. निम्नलिखित का मानदण्ड के अनुसार पन्द्रह गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के बीच शेष राशि का आवंटन:

मानदण्ड	अधिभार (%)	
(I) जनसंख्या (1971)		60%
(II) प्रतिव्यक्ति आय, जिसमें		25%
(क) विचलन विधि के अनुसार जिनमें केवल वे राज्य आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति एसडीपी राष्ट्रीय औसत से कम है	20%	20%
(ख) "अंतर" विधि के अनुसार सभी 15 राज्य	5%	
(III) कार्य निष्पादन जिसमें		7.5%
(क) पूर्व गाडगिल फार्मूले में यथापरिभाषित "कर प्रयास" के अनुसार	2.5%	
(ख) पूर्व संशोधित फार्मूले में यथापरिभाषित राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार, और	2.5%	
(ग) राष्ट्रीय लक्ष्यों के बारे में कार्यनिष्पादन के अनुसार	2.5%	
(IV) विशेष समस्याएं		7.5%

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कतिपय कार्यक्रमों के बारे में कार्य निष्पादन के मानदण्ड के तहत अनुमोदित फार्मूले में चार लक्ष्य शामिल हैं, जैसे:— (I) जनसंख्या नियंत्रण (II) निरक्षरता उन्मूलन, (III) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, और (IV) भूमि सुधार में सफलता।

उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित की गई धनराशि

2801. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि वित्तीय वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश को उसकी वार्षिक योजनाओं के लिए